



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 37-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018 (BHADRA 20, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

मुख्य सचिव कार्यालय
सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रोटोकोल शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 5 सितम्बर, 2018

संख्या 16/27/2017-4प्रो०— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रोटोकोल शाखा) की अधिसूचना संख्या 16/27/2017-4प्रो० दिनांक 16 अप्रैल, 2018 में निम्न संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रोटोकोल शाखा) अधिसूचना संख्या 16/27/2017-4प्रो०, दिनांक 16 अप्रैल, 2018 में, पैरा 4 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पैरा 4 के शीर्ष (ख) :

“यह स्कीम हरियाणा के ऐसे निवासियों के लिए लागू होंगी, जिन्होंने आपातकाल की अवधि के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और संघर्ष किया तथा चाहे उन्हें किसी अन्य राज्य सरकार से अन्य पैशन मिल रही हो, वह भी पात्र होंगे।”

डी०एस० डेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

CHIEF SECRETARY'S OFFICE
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
PROTOCOL BRANCH

Notification

The 5th September, 2018

No. 16/27-2017-4Pro.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department (Protocol Branch) Notification No. 16/27/2017-4Pro. dated 16th April, 2018, namely.

Amendment

In the Haryana Government, General Administration Department (Protocol Branch), Notification No. 16/27/2017-4Protocol, dated 16th April, 2018 the following amendment are made:-

Para 4 (b) amended as :

“4 (b) Emergency sufferers, getting pension or honorarium of any kind from any other State Government will also be eligible. Thus, getting pension from any other State Government would not be a bar for entitlement of pension to an otherwise eligible person under the scheme.”

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.